# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)
PART II — Section 3 — Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] No. 197] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 2007/वैशाख 5, 1929 NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 2007/VAISAKHA 5, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2007

सं. 24/2007—को.उ.शु. (गै,टै.)

सा.का.नि. 309(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है यथा :—

- 1. (1) इन नियमों को सेनवेट क्रेडिट (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2007 कहा जाएगा।
  - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से परिवर्तित होंगे।
- 2. सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 में, नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा यथा :-

"इन नियमों में निहित किसी भी विरोधी बातों के बावजूद, जहां कि विनिर्माता ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 20/2007 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25 अप्रैल, 2007 के दृष्टि से अतिम उत्पादों को क्लियर कर दिया है और उक्त अतिम उत्पाद पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक आदानों पर लगाए गए शुल्क का भुगतान करने के लिए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करने में अक्षम रहता है, उन अतिम उत्पादों के अलावा जिन पर छूट है या शून्य दर से शुल्क लगाया जाता है, तो केन्द्र सरकार ऐसी प्रक्रिया, शर्तों और सीमाओं के अधीन जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे क्रेडिट के वापस करने की अनुमति दे सकती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनार्थ शुल्क का तात्पर्य ऐसे शुल्क से हैं जो इस नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट है।"

[फा. सं. 267/45/2007-सी एक्स-8]

राहुल नांगरे, अवर सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2007

#### No. 24/2007-Central Excise (NT)

G.S.R. 309(E).— In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Fourth Amendment) Rules, 2007.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:—

"5A.-Refund of CENVAT credit to units in specified areas.— Notwithstanding anything contrary contained in these rules, where a manufacturer has cleared final products in terms of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 20/2007-Central Excise, dated the 25th April, 2007 and is unable to utilize the CENVAT credit of duty taken on inputs required for manufacture of final products specified in the said notification, other than final products which are exempt or subject to nil rate of duty, for payment of duties of excise on said final products, then the Central Government may allow the refund of such credit subject to such procedure, conditions and limitations, as may be specified by notification.

Explanation: For the purposes of this rule, "duty" means the duties specified in sub-rule (1) of rule 3 of these rules."

[F.No.267/45/2007-CX.8]

RAHUL NANGARE, Under Secv.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2007

## सं. 25/2007-के,उ,शु, ( गै.टै. )

सा.का.नि. 310(अ).—सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालनार्थ केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 25 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं. 20/2007 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में विहित शर्तों के अध्यधीन उपयोग में न ली गई सेनवेट क्रेडिट के प्रतिदाय का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया विहित करती है,—

- (क) विनिर्माता के कारखाने पर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त के पास एक घोषणा फाइल करेगा जिसमें उद्ग्रहणीय शुल्क की दर और विनिर्माणकारी अथवा संसाधक सूत्र के साथ मात्रा के प्रांतनिर्देश की विशिष्टि या उस सामग्री का अनुपात जिसमें मात्रा का वास्तविक रूप से उपयाग किया जाएगा, के साथ-साथ मात्रा के लिए प्रस्तावित तैयार माल का वर्णन होगा। उक्त घोषणा में विनिर्मित और निकासित किए जाने वाले तैयार माल के संबंध में टेरिफ वर्गीकरण, अथवा ऐसे उपयोग में ली गई सामग्रियों पर संदत अथवा संदेय शुल्क की दर, शब्दों और संख्या दोनों निहित होंगे। तथापि यदि घोषणा में दिया गया कोई विवरण में कोई परिवर्तन किया जाता है तो विनिर्माता को संशोधित घोषणा दायर करनी होगी।
- (ख) विनिर्माता को धन वापसी के दावे के लिए सहायक आयुक्त या उपायुक्त जैसी भी स्थिति हो, के पास अगले महीने की 7 तारीख तक एक विवरण प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए गए हों यथा आदानों के प्रारम्भिक शेष की मात्रा, इस माह के दौरान प्राप्त आदानों की मात्रा, उसका मूल्य, उस पर भुगतान किया गया या भुगतान योग्य शुल्क, लिए गए सेनवेट क्रेडिट की राशि, इस माह के दौरान प्रयुक्त धनराशि की मात्रा, विनिर्मित अंतिम उत्पाद की मात्रा, इस माह के अंत में भण्डार में रखे अधानों की मात्रा, अंतिम उत्पाद पर शुल्क का भुगतान किए जाने के लिए प्रयुक्त सेनवेट क्रेडिट की राशि और शेष रही सेनवेट क्रेडिट की राशि।
- (ग) सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जैसा मामला हो, ऐसी जांच के बाद आवश्यक समझने पर विवरण प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की अविध के अंदूर समीक्षाधीन महीने के अंत में उपयोग नहीं किए गए क्रेडिट की शेष राशि, यदि कोई हो, विनिर्माता को वापस कर देंगे।

(घ) यदि जांच में कोई विलम्ब होने की सम्भावना हो तो सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जैसा मामला हो, समीक्षाधीन महीने के बाद के महीने के 30वें दिन अस्थाई आधार पर 80 प्रविशत राशि वापस कर देंगे।

[फा. सं. 267/45/2007-सी एक्स-8]

राहुल नांगरे, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi; the 25th April, 2007

#### No.25/2007-Central Excise (NT)

G.S.R. 310(E).—In exercise of the powers conferred by rule 5A of the CENVAT Credit Rules, 2004, the Central Government hereby prescribes the following procedure for claiming refund of unutilised CENVAT credit, subject to the conditions prescribed in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 20/2007-Central Excise, dated the 25th April, 2007,—

- (a) The manufacturer shall file a declaration with the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over the factory of manufacture describing the finished goods proposed to be manufactured along with their rate of duty leviable and manufacturing or processing formula with particular reference to quantity or proportion in which the materials are actually used as well as the quality. The declaration shall also contain the tariff classification, rate of duty paid or payable on the materials so used, both in words and figures, in relation to the finished goods to be manufactured and cleared. However, if any particulars given in the declaration have undergone any changes, the revised declaration shall be filed by the manufacturer;
- (b) The manufacturer shall submit a statement containing details namely quantity of opening balance of inputs, quantity of inputs received during the month, value thereof, duty paid or payable thereon, amount of CENVAT Credit taken, quantity of inputs used during the month, quantity of final products manufactured, quantity of inputs lying in stock at the end of the month, amount of Cenvat credit utilised for payment of duty on the final product and amount of CENVAT credit lying in balance to the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, by the 7th day of the next month for claiming refund;
- (c) The Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, after such verification, as may be deemed necessary, may refund the balance amount of unutilised credit, if any, at the end of the month under consideration to the manufacturer within a period of 3 months from the date of receipt of the statement; and
- (d) If there is likely to be any delay in the verification, the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, shall refund 80% of the amount on provisional basis by the 30th day of the month following the month under consideration.

[F.No. 267/45/2007-CX. 8]

RAHUL NANGARE, Under Secy.